इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 8 अंक सं. :6 जनवरी, 2016 पृष्ठों की सं 14

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मुख्य घटनाएं --- 2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां-- 2
बैंकिंग जगत की घटनाएं-- 4
विनियामकों के कथन -- 6
बीमा --6
अर्थव्यवस्था ---7
नयी नियुक्तिया -- 7
उत्पाद एवं गठजोड -- 8
विदेशी मुद्रा --- 8
शब्दावली --------------------------------- --------------------- ------9
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ---------------------------------------10
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां --10
संस्थान समाचार --10
बाज़ार की खबरें --13

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

2016 से 2 लाख रुपये से अधिक के सभी लेनदेनों के लिए पैन अनिवार्य

यह निर्णय लिया गया है कि भुगतान की विधि चाहे जो भी क्यों न हो, 2 लाख रुपये की रकम से अधिक के लेनदेनों के लिए स्थायी खाता संख्या (PAN) को उद्धृत करना आवश्यक होगा। विधिसम्मत लेनदेनों के सम्बन्ध में अनुपालन के दायित्व और उच्चतर मूल्य वाले लेनदेनों से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता के बीच संतुलन लाने के लिए सरकार ने कुछेक ऐसे लेनदेनों की मौद्रिक सीमाएं भी बढ़ा दी हैं, जिनमें स्थायी खाता संख्या को उद्धृत करना आवश्यक हो। नियमों में ये परिवर्तन 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगे। नियमों में इन परिवर्तनों से कर -पाश को व्यापक बनाने में सहायता प्राप्त होने की आशा है। उनसे काले धन पर रोक लगाने और नकदी रहित अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रस्थान करने में भी सहायता प्राप्त होने की आशा है।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

विदेशी उधार के मानदंड शिथिल

पिछले 10 वर्ष की स्थूल-आर्थिक घटनाओं तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) प्रणाली को नियंत्रित करने में प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार से परामर्श करके वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार □ांचे का पुनरीक्षण किया है। उक्त ढांचे में यह विनिर्देशन था कि बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रयोज्य दिशानिर्देशों के अनुपालन में हो, यह सुनिश्चित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व सम्बन्धित उधारकर्ता का है। विदेशी मुद्रा में बाह्य वाणिज्यिक उधार के मामले में 3 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले कम मूल्य के बॉण्डों की सीमा बढ़ाकर 50 मिलियन अमरीकी डालर कर दी गई है। 50 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के बाह्य वाणिज्यिक उधारों के मामले में न्यूनतम परिपक्वता अवधि पांच वर्ष होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पारस्परिक मुद्रा में भावी सौदों तथा शेयर बाज़ार में खरीदी-बेची जाने वाली विकल्प संविदाओं की शुरुआत की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्राओं में एक्सपोजरों के प्रत्यक्ष प्रतिरक्षण में समर्थ बनाने और बाज़ार के सहभागियों द्वारा पारस्परिक मुद्रा (cross-currency) रणनीतियों को निष्पादित किए जाने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शेयर बाज़ार मे खरीदी--बे□□ □ने वाली व्युत्पन्नियों (derivatives) के बाज़ार में पारस्परिक मुद्रा-युग्मों की शुरुआत कर दी है। आरंभ किए गए पारस्परिक मुद्रा-युग्म थे- यूरो - अमरीकी डालर, पौंड - स्टर्लिंग - अमरीकी डालर तथा अमरीकी डालर - जापानी येन। मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ारों को तत्काल प्रभाव से अमरीकी डालर - भारतीय रुपये में विकल्प संविदा की वर्तमान व्यवस्था के अतिरिक्त यूरो - भारतीय रुपये, जीबीपी - भारतीय रुपये और जापानी येन - भारतीय रुपये में शेयर बाज़ार में खरीदी-बेची जाने वाली मुद्रा विकल्प संविदाएं भी प्रदान करने की अनुमति है।

मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मोबाइल बैंकिंग में समर्थ बनाने हेतु राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (NFS) में सहभागिता करने वाले सभी बैंकों के लिए अपनी-अपनी एटीएम स्विचों में ग्राहक पंजीकरण में समर्थ बनाने के लिए अधिकतम 31 मार्च, 2016 तक आवश्यक परिवर्तन करना आवश्यक बना दिया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने राष्ट्रीय वित्तीय स्विच पर मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण सेवा / विकल्प विकसित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को मोबाइल बैंकिंग के लिए इंटरनेट बैंकिंग, आईवीआर, फोन बैंकिंग आदि सहित अन्य चैनलों के माध्यम से भी ग्राहक पंजीकरण सुविधा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। चूंकि मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु ग्राहक पंजीकरण एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा होती है, बैंकों को उनके ग्राहकों के बीच मोबाइल बैंकिंग सेवाओं और विकल्पों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने हेतु ग्राहक पंजीकरण के लिए उपलब्ध बहुविध चैनलों का भी उपयोग करना चाहिए।

बैंक आधार दर का निर्धारण निधियों की सीमांत लागत के अनुसार करेंगे : भारतीय रिज़र्व बैंक

1 अप्रैल, 2016 से स्वीकृत किए जाने वाले सभी रुपया ऋण तथा नवीकृत ऋण सीमाओं का मूल्य-निर्धारण निधियों की सीमांत लागत, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) के कारण ऋणात्मक प्रभार (negative carry), परिचालन लागत तथा परिपक्वता काल प्रीमियम के समावेश वाली निधियों की सीमांत लागत पर आधारित उधार दर के अनुसार किया जाएगा। बैंक अपने अस्थिर दर वाले ऋणों के सम्बन्ध में ब्याज पुनर्निर्धारण तिथियां विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। बैंकों को या तो ऋणों / ऋण सीमाओं की स्वीकृति तिथि या फिर निधियों की सीमांत लागत पर आधारित उधार दर (MCLR) से सम्बद्ध पुनर्नियतन तिथियों के साथ ऋण प्रदान करने का विकल्प प्राप्त होगा।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने खुले बाज़ार के परिचालनों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये मूल्य के बॉण्ड खरीदे

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने खुले बाजार के परिचालनों (OMOs) के एक अंग के रूप में गौण बाज़ार से 10,000 करोड़ रुपये के बॉण्ड खरीदे। चार बॉण्डों की नीलामी में सहभागियों द्वारा प्रदान की गई कुल रकम 54,413.30 करोड़ रुपये की थी। उक्त नीलामी में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2018, 2019 और 2024 में परिपक्व होने वाले बॉण्डों की खरीद क्रमश: 7.4441%, 7.6181% तथा 7.9051% न्यूनतम प्रतिफल पर की। किन्तु उसने 2030 में परिपक्व होने वाले बॉण्डों के लिए कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन से सम्बन्धित मध्य-अवधि मार्ग पर समिति की रिपोर्ट जारी की

भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मोहन्ती की अध्यक्षता वाली वित्तीय समावेशन से सम्बन्धित मध्य-अवधि मार्ग पर समिति ने यह सुझाव दिया है कि सरकार से व्यक्ति (G2P) को नकद अंतरण के बिना सार्थक वित्तीय समावेशन संभव ही नहीं है। उक्त समिति ने अर्थव्यवस्था को मध्य अवधि में बनाए रखने योग्य वित्तीय समावेशन के मार्ग पर लाने के लिए अभिशासन प्रणाली में सुधार लाने, ऋण की मूलभूत सुविधा को सुदृढ़ बनाने तथा सरकार के सामाजिक नकद अंतरण को बढ़ाने के लिए कतिपय अन्य सिफारिशें भी की हैं, ताकि गरीबों की वैयक्तिक प्रयोज्य आय को बढ़ाया जा सके।

परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा का भारतीय रिज़र्व बैंक का सर्वेक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिसम्बर, 2015 के लिए परिवारों की उन तिमाही मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं के सर्वेक्षण की शुरुआत कर दी है, जिनके परिणाम नीति-निर्धारण के लिए उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। उक्त सर्वेक्षण में परिवारों से आगामी तीन महीनों में और उसके साथ ही आगामी एक वर्ष में मूल्यों (सामान्य कीमतों और उसके साथ ही विशिष्ट उत्पाद समूहों) में परिवर्तनों के सम्बन्ध में गुणात्मक प्रत्युत्तर तथा वर्तमान, तीन माह के बाद और एक वर्ष बाद वाली मुद्रास्फीति की दरों के सम्बन्ध में मात्रात्मक प्रत्युत्तर प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। ये मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं सर्वेक्षण में शामिल परिवारों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होते हैं तथा वे उनके वैयक्तिक उपभोग समूहों पर आधारित होते हैं।

विदेशी मुद्रा के मामलों के सम्बन्ध में स्टार्ट -अपों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की हेल्पलाइन

सद्य: स्थापित (स्टार्ट-अप) उद्यम आम तौर पर निवेश से सम्बन्धित सहित सीमा-पार वाले व्यापक श्रेणी के लेनदेन करते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियामक ढांचे की परिधि में आने वाले सीमा-पार के लेनदेन करने हेतु सद्य: स्थापित उद्यमों (स्टार्ट-अपों) को मार्गदर्शन / सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन (helpstartup@rbi.org.i) सृजित कर रखी है। मार्गदर्शन की मांग करते समय उद्यमों को चाहिए कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक को पूरी सूचना प्रदान करें तथा विदेशी मुद्रा प्रबन्ध विनियमनों से सम्बन्धित उन विशिष्ट मुद्दों का उल्लेख करें जिनके सम्बन्ध में उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक से मार्गदर्शन की जरूरत है। इससे हेल्पलाइन पर कार्यरत कर्मचारी सामयिक एवं प्रभावी सूचना प्रदान करने में समर्थ होगा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को और उधार देना होगा

वित्तीय समावेशन कार्यसूची के अनुसरण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दिशानिर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 75% बकाया अग्रिमों का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए होना आवश्यक होगा, जिसमें कुल बकाये के 15 प्रतिशत की सीमा के साथ मौजूदा श्रेणियों के अलावा मध्यम उद्यमों,सामाजिक मूलभूत सुविधा और नवीकरणीय ऊर्जा को ऋणों का भी समावेश है। ये संशोधित दिशानिर्देश 1 जनवरी, 2016 से लागू हो जाएंगे। इस तिथि से पहले वाले दिशानिर्देशों के तहत स्वीकृत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों को चुकौती / नवीकरण किए जाने तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत वर्गीकृत किया जाना □ारी रहेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक शेयर बाज़ार में खरीदी-बेची जाने वाली व्युत्पन्नियों में हस्तक्षेप करने हेतु तैयार

भारतीय रिज़र्व बैंक घरेलू विदेशी मुद्रा बाज़ार में जब कभी आवश्यकता पड़ती है, अतिशय अस्थिरता को नियंत्रित करने तथा बाज़ार में व्यवस्थित स्थितियां बनाए रखने हेतु हस्तक्षेप करता है। एक अतिरिक्त उपाय के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने आवश्यकता होने पर शेयर बाज़ार में खरीदी-बेची जाने वाली व्युत्पन्नी (derivatives) खण्ड में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया है। शेयर बाज़ार में खरीदी-बेची जाने वाली व्युत्पन्नी में हस्तक्षेप के आंकड़ों को भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन में ठीक उसी प्रकार प्रकाशित किया जाएगा □ैसा कि वह काउण्टर पर (OTC) किए जाने वाले लेनदेन में (हस्तक्षेप में) किया जाता है।

विविध मुद्दों पर चर्चा करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की बैंकरों के साथ बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के चुनिंदा बैंकरों के साथ मुंबई में एक बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम जी. राजन ने की। बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उप गवर्नर श्री

आर. गांधी और श्री एस.एस. मूंदड़ा भी उपस्थित रहे। बैंकिंग क्षेत्र की ओर से इस बैठक में बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपस्थित रहे। उक्त बैठक के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकरों ने बैंकों की आस्ति गुणवत्ता सहित विविध मुद्दों और बैंकों के तुलनपत्रों में सुधार लााने से सम्बन्धित आगे के मार्ग पर चर्चा की।

विनियामकों के कथन

डॉ. राजन ने कारपोरेट जोखिमों पर चिंता व्यक्त की

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने कहा है कि विवेकसंगत नीतिगत उपायों और हितकर पण्य कीमतों के कारण जहां भारत उभरते बाज़ार के कई एक समकक्षों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में लगता है, वहीं कुछेक ऐसे मुद्दे भी मौजूद हैं जिन पर उभरते जोखिमों से निपटने की तैयारी करते समय हमारे लिए अब भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। डॉ. रघुराम राजन ने कारपोरेट क्षेत्र की कमजोरियों तथा उनके. कमजोर तुलनपत्रों के वित्तीय प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभावों पर सघन निगरानी रखे जाने का आह्वान किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि साइबर सुरक्षा महज एक परिचालनात्मक चिंता की बजाय अधिकांशत: एक रणनीतिक मुद्दा होने के कारण एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी, जिस पर खतरों एवं समाधानों की बोर्ड के स्तर पर समझ आवश्यक होती है।

भारत में छाया बैंकिंग : श्री आर. गांधी

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गांधी ने कहा है कि कुछेक आर्थिक गतिविधियों में अपेक्षाकृत अधिक बहिर्मुखता निहित होती है और वित्तीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें निहित बहिर्मुखताएं ऐसी होती हैं जिनके लिए उपभोक्ताओं को संरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रणालीगत स्थिरता, सुरक्षा एवं बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की सुदृढ़ता के हित में गहन विनियमन एवं पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। अतएव उन प्रणालीगत जोखिम कारकों (यथा- परिपक्वता और चलनिधि रूपांतरण एवं उत्तोलन) जो बैंकेतर क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण के तीव्र विस्तार से पैदा हो सकती है, में सजग और निरंतर निगरानी की जरूरत पड़ती है।

बीमा

इर्डाई व्यापार ऋण बीमा मानदंडों में परिवर्तन के पक्ष में

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बीमा विनियामक भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने व्यापार ऋण बीमा से सम्बन्धित दिशानिर्देशों में परिवर्तन प्रस्तावित किया है। व्यापार ऋण बीमा से सम्बन्धित दिशानिर्देशों में संशोधन के सम्बन्ध में एक्सपोजर मसौदे में यह कहा गया है कि अर्थव्यवस्था, विशेषत: सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम क्षेत्र में परिवर्तनों से व्यापार ऋण की आवश्यकता बढ़ गई है और ऋण बीमा क्षेत्र का विषय क्षेत्र कई गुना बढ़ गया है।

अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था में पुनरुत्थान के संकेत दिखाई दे रहे हैं : वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि स्थूल-आर्थिक संकेतकों ने आशावादी प्रवृत्ति दिखानी आरंभ कर दी है तथा ढांचागत सुधार वृद्धि में योगदान कर रहे हैं। आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए राज्य मंत्री (वित्त) श्री जयंत सिन्हा ने रा□कोषीय समेकन के मार्ग पर डटे रहने का प्रयास करते हुए सामाजिक क्षेत्र पर खर्चों को बढ़ाने तथा पूंजीगत व्यय को भी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

नयी नियुक्तियां

नाम	पदनाम / संगठन
श्री पार्थसारथी मुखर्जी	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, लक्ष्मी विलास बैंक
श्री ए. के. जैन	कार्यपालक निदेशक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक
श्री शांतनु सेनगुप्ता	भारत में उपभोक्ता बैंकिंग प्रमुख, डीबीएस बैंक
श्री पास्कल बोइलट	मुख्य सूचना अधिकारी एवं परिचालन, कारपोरेट एवं निवेश दल के प्रमुख ड्यूश बैंक
श्री डिडियर वॉन डैनीकेन	निजी बैंकिंग एवं संपदा प्रबन्धन के ग्लोबल प्रमुख, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
श्री टॉप्सी मैथ्यू	दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व राष्ट्रों के संघ के लिए कारपोरेट वित्त के प्रधान, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
श्री थॉमस जोसेफ के.	कार्यपालक उपाध्यक्ष, प्रशासन, साउथ इंडियन बैंक
श्री अरुण कुमार पद्मनाभन	मुख्य परिचालन अधिकारी और वरिष्ठ ग्रुप अध्यक्ष, परिचालन एवं सेवा सुपुर्दगी, येस बैंक

श्री नीरज धवन	ग्रुप प्रेसिडेंट एवं मुख्य जोखिम अधिकारी (खुदरा एवं कारबार), येस बैंक
श्री राजन पेंटल	ग्रुप हेड, खुदरा उधार, खुदरा बैंकिंग आस्ति, येस बैंक

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	**जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ**	**उद्देश्य**
भारतीय रिज़र्व बैंक	प्रूडेंसियल रेग्यूलेशन अथॉरिटी एण्ड फाइनैंसियल कंडक्ट अथॉरिटी, यू.के.	पर्यवेक्षी सहयोग तथा पयवेक्षी सूचना के आदान-प्रदान के लिए।
भारतीय निर्यात-आयात (एक्जिम) बैंक	एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ मलेसिया बरहाद	दोनों बैंकों में हितकर परियोजनाओं की सहायता करने के लिए वित्तीयन, गारंटी प्रदान करने तथा अन्य वित्तीयन व्यवस्थाओं में सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए।
देना बैंक	एसबीआई लाइफ इंश्योरेस कम्पनी	उसके गृह ऋण उधारकर्ताओं को एक समूह जीवन सुरक्षा - देना गृहस्वामी सुरक्षा योजना प्रदान करने के लिए।
	□सीबी-इंडिया लि.	उपकरण वित्तीयन व्यवसाय के लिए।
कर्नाटका बैंक लिमिटेड	यूनीवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी	केबीएल सुरक्षा, एक समूह वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत करने के लिए।
येस बैंक	इस्पिरिट	भारतीय वित्त-तकनीक स्टार्ट-अपों को परामर्श देने तथा उन्हें येस बैंक के साथ भागीदारी में मार्गदर्शन प्रदाने करने के लिए।
कैथलिक सीरियन बैंक	□□	ग्राहकों को निधि अंतरण एवं भुगतान सेवाओं के लिए तत्काल धन प्रेषण में समर्थ बनाने के लिए

विदेशी मुद्रा

जनवरी, 2016 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की न्यूनतम दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.87650	1.16200	1.42740	1.61620	1.74950
जीबीपी	0.73070	1.1026	1.3121	1.4682	1.5943

यूरो	-0.04820	- 0.015	-0.086	0.191	0.332
जापानी येन	0.13380	0.129	0.123	0.143	0.179
कनाडाई डालर	0.93000	0.843	0.955	1.074	1.204
आस्ट्रेलियाई डालर	2.25200	2.217	2.265	2.498	2.620
स्विस फ्रैंक	0.65000	-0.605	-0.538	-0.443	-0.278
डैनिश क्रोन	0.15300	0.2170	0.3351	0.4909	0.6680
न्यूजीलैंड डालर	2.78000	2.860	3. 000	3.150	3.290
स्वीडिश क्रोन	0.27200	-0.099	0.156	0.447	0.734
सिंगापुर डालर	1.87000	2.070	2.290	2.465	2.595
हांगकांग डालर	0.75000	1.060	1.270	1.450	1.590
म्यामार	3.82000	3.860	3.900	3.960	4.030

स्रोत : www.fedai.0rg.in

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**27 नवम्बर, 2015 के दिन**	**27 नवम्बर, 2015 के दिन**
	बिलियन् रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	23, 216,4 9	3,52, 049..9
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	21, 692.4	3,29, 191.6
ख) सोना	1,172, 2	17, 543. 8
ग) विशेष आहरण अधिकार	265, 7	4, 013.4
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	86.1	1, 301.1

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

शब्दावली

खुले बाज़ार के परिचालन (OMOs)

खुले बाज़ार के परिचालन (OMOs) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा बाज़ार में रुपये की अनिरुद्धता (liquidity) की स्थितियों को स्थायी आधार पर समायोजित करने के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूतियों की बाज़ार को बिक्री / खरीद के रूप में किए जाने वाले बाज़ार के परिचालन होते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक को जब ऐसा लगता है कि बाज़ार में नकदी का आधिक्य हो गया है, तो वह प्रतिभूतियों की बिक्री का आश्रय लेता है जिसके द्वारा वह रुपये की अनिरुद्धता को अवशोषित कर लेता है। इसी प्रकार चलनिधि की स्थितिं के कठोर होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक

बाज़ार से प्रतिभूतियों की खरीद करेगा, जिसके द्वारा वह बाज़ार में चलनिधि (नकदी) जारी करता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

ऋण जोखिम न्यूनीकरण

एक्सपोजर को नकदी या प्रतिभूतियों से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप में संपार्श्वीकृत करके अथवा अन्य पक्ष द्वारा गारंटीकृत करवा कर ऋण जोखिम को न्यूनीकृत करने हेतु प्रयुक्त तकनीकें।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

फरवरी, 2016 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रमों के नाम	तिथियां	स्थल
1	अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	1-2- 2016 से 6-2-2016	मुंबई
2	वसूली प्रबन्धन पर कार्यक्रम	8-2- 2016 से 10-2-2016	मुंबई
3	डीबीएस के अधिकारियों के लिए विदेशी मुद्रा कार्यक्रम	8-2- 2016 से 9-2-2016	मुंबई
4	परियोजना वित्त में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम - आईँआईँबीएफ-आईएफएमआर के 25वें बैच के लिए कैम्पस प्रशिक्षण	29-2-2016 से 5-3- 2016	चेन्नै (आईएमएफआर कैम्पस)

संस्थान समाचार

11

आईआईबीएफ का ऐंड्रोइड मोबाइल ऐप

आईआईबीएफ के उपाध्यक्ष और देना बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री अश्वनी कुमार द्वारा आरंभ किया गया आईआईबीएफ का ऐंड्रोइड मोबाइल ऐप डाउनलोड के लिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस अनुप्रयोग को डाउनलोड करने के बाद प्रयोक्ता के लिए आरंभ करने हेतु मूलभूत जानकारी (सदस्य का नाम, ई-मेल और मोबाइल संख्या) प्रदान करना आवश्यक होता है। इस अनुप्रयोग का उपयोग करते हुए अभ्यर्थी / सदस्य संस्थान, सदस्यता, परीक्षाओं, प्रशिक्षण, पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में समर्थ होगा।

आईआईबीएफ द्वारा सोशल मीडिया में प्रवेश

संस्थान फेसबुक और यूट्यूब पर मौजूद है। यह कदम बैंकिंग एवं फाइनैंस में संस्थान के पाठ्यक्रमों को प्रासंगिक एवं अद्यतन बनाने के लिए उनसे सूचनाएं /. प्रति-सू□ना प्राप्त करने में उसकी सहायता करेगा।

अपने ग्राहक को जानिए / धन-शोधन निवारण तथा ग्राहक सेवा परीक्षा

संस्थान अप्रैल 2016 और उसके बाद से अपने ग्राहक को जानिए / धन-शोधन निवारण तथा ग्राहक सेवा परीक्षाओं का तिमाही आधार पर आयोजन करेगा। 2016 की पहली तिमाही के लिए कार्यक्रम निम्नानुसार है :

परीक्षा	विषय	अप्रैल, 2016 की परीक्षा की तिथि	पंजीकरण हेतु मुक्त अवधि
धन-शोधन निवारण- अपने ग्राहक को जानिए प्रमाणपत्र परीक्षा	धन-शोधन निवारण- अपने ग्राहक को जानिए	10-4-201600 ब□	08-01-2016 से 08-02-2016 तक
ग्राहक सेवा और बैंकिंग संहिता एवं मानक में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	ग्राहक सेवा और बैंकिंग संहिता एवं मानक	10-04-2016 समय : पूर्वान्ह 11.30 ब□	08-01-2016 से 08-02-2016 तक

अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

परीक्षा के लिए दिशानिर्देशों / महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान द्वारा किसी कैलेंडर वर्ष के मई / जून माह के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में प्रश्नपत्र में समावेश के लिए विनियामक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों और बैंकिंग एव वित्त के क्षेत्र में केवल पिछले वर्ष की 31 दिसम्बर तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

संस्थान द्वारा किसी कैलेंडर वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर माह के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में प्रश्नपत्र में समावेश के लिए विनियामक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों और बैंकिंग एव वित्त के क्षेत्र में केवल पिछले वर्ष की 31 दिसम्बर तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों और अन्य स्रोतों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपनी वेब साइट पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

आलेखों / प्रस्तावों हेतु आमंत्रण

संस्थान वर्ष 2015-16 के लिए सूक्ष्म आलेख / स्थूल प्रस्ताव आमंत्रित करता है। आलेख / प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2016 है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

हीरक जयंती और सी.एच. भाभा बैंकिंग विदेशी अनुसंधान एवं फेलोशिप (DJCHBBORF)

संस्थान वर्ष 2015-16 के लिए हीरक जयंती और सी.एच. भाभा बैंकिंग विदेशी अनुसंधान एवं (अध्येतावृत्ति) फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेधन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2016 है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 /1998 के अधीन पंजीकृत

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

7.5
7
6.5
6
5.5
5

01/12/2015 04/12/2015 05/12/2015 07/12/2015 09/12/2015 16/12/2015 19/12/2015 21/12/2015 23/12/2015 31/12/2015

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, दिसम्बर, 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

110.00
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00

01/12/2015 03/12/2015 07/12/2015 10/12/2015 14/12/2015 16/12/2015 18/12/2015 22/12/2015 28/12/2015 31/12/2015

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

14

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

26400
26200
26000

25800
25600
25400
25200
25000
24800

01 दिस.15 03 दिस.15 07 दिस..15 09 दिस.15 15 दिस. 15 17 दिस. 15 18 दिस.. 15 24 दिस..15
28 दिस. 15 31 दिस.15

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (BSE)

डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल-II,, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. जे. एन. मिश्र

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न जनवरी, 2016